



युवा देख सकेंगे बिजली पासी की वीरता



www.jagran.com

परेशानी

सोलर पॉवर प्लांट लगा कर रहे सब्सिडी का इंतजार, नेडा कार्यालय के चक्कर काट रहे लोग

सूरज से घर तो रोशन हुआ, पर खाते में नहीं दौड़ा करंट

रुमा सिन्हा • लखनऊ

छत पर सोलर पावर प्लांट लगा कर बिजली पैदा करने वाले राजधानी के जागरूक उपभोक्ता निराश हैं। वजह यह है कि सोलर पावर प्लांट लगाकर उन्हें अबाध बिजली तो मिल रही है लेकिन जेब खाली है। बीते साल भर से वह खाते में सब्सिडी आने की बाट जोह रहे हैं।

इंदिरा नगर, सीतापुर रोड, आलमबाग, गोमती नगर आदि इलाकों के सैकड़ों उपभोक्ताओं ने अपने घरों की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाए। मकसद यह था कि महंगी बिजली के बिल से जहां राहत मिले, वहीं पर्यावरण को भी राहत मिल सके। इंदिरा नगर निवासी गनपत प्रसाद, संजय तिवारी, अमित कुमार गुप्ता, शारदा गंगवार सहित कई लोगों ने अपनी छत पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराई। उम्मीद थी कि अपने हिस्से की बिजली बनाकर हर माह बिजली के खर्च से मुक्ति

मिल जाएगी। वहीं, खर्च की गई रकम में से सब्सिडी का हिस्सा वापस मिल जाएगा। इससे जेब को भी राहत मिलेगी। गनपत प्रसाद बताते हैं कि तीन किलोवाट का प्लांट आठ मार्च को लगवाया था। प्लांट लगवाने में कुल दो लाख 14 हजार रुपये का व्यय आया था। केंद्र सरकार से 45 हजार और राज्य सरकार से 30 हजार रुपये सब्सिडी के मिलने थे। वह कहते हैं कि कहा गया था कि तीन माह में सब्सिडी खाते में आ जाएगी। सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं लेकिन 11 माह बीतने के बाद भी सब्सिडी नहीं मिली है।

सीतापुर रोड निवासी धनीराम वर्मा कृषि विभाग से रिटायर हुए हैं। बीती अप्रैल में उन्होंने चार किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगवाया था जिसपर दो लाख 85 हजार रुपये का व्यय आया था। इस पर एक लाख 30 हजार रुपये सब्सिडी दी जानी थी। की बार संपर्क किए जाने के बाद भी सब्सिडी नहीं मिल पाई है।



इंदिरानगर कॉलोनी में संजय तिवारी के घर की छत पर लगा सोलर पॉवर प्लांट

ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों लोग हैं जो घर को तो रोशन कर रहे हैं लेकिन जेब खाली है। यह लोग कभी लगाने वाली कंपनी से तो कभी नेडा कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं।

भारत सरकार से वर्ष 2018-19 के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। सप्ताह भर में ऐसे उपभोक्ताओं को जिन्होंने इस दौरान सोलर पावर प्लांट लगवाया था, सब्सिडी जारी कर दी जाएगी। हालांकि वर्ष 2017-18 की सब्सिडी के लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा।

आलोक कुमार
सचिव, यूपीनेडा